अध्याय 15

शिक्षा

'सर्वोपरि शिक्षा वह है जो न केवल हमें ज्ञान उपलब्ध कराती है बल्कि सभी जीवों के साथ हमारे जीवन का सदभाव स्थापित करती है।' **रबिन्द्र नाथ टैगोर**

किसी देश का भविष्य उसके विद्यालयों की कक्षा में गढ़ा जाता है। एक प्रभावी शिक्षा प्रणाली लागू करना, शिक्षा के प्रति समर्पित दृष्टिकोण के साथ, जैसे सब के लिए समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना, अनुकूल पाठ्यक्रम पर जोर देने के साथ शिक्षा को आनंदप्रद अनुभव बनाने की शैक्षणिक तकनीकों और संवाद प्रक्रिया शामिल करने पर आधारित है। इसलिए शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य रचनात्मकता, निर्णय लेने की क्षमता संप्रेषण क्षमता, समन्वय, नेतृत्व और टीमवर्क की भावना विकसित करना होना चाहिए।

1.2 नई शिक्षा नीति 2020 भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में बहुविषयक और अनुसंधान के नियमन, प्रशासन और संवर्द्धन प्रणालीबद्ध और संस्थागत सुधार पर जोर देती है। इसके अलावा शिक्षा नीति पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सुलभता और जवाबदेही को बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार पहले से ही समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और वर्ष 2030 (जैसा कि सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी–04)–2030 एजेंडे में दर्शाया गया है।) तक सबके लिए जीवनपर्यन्त के अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास कर रही है।

1.3 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार शिक्षा क्षेत्र में भारी सार्वजनिक निवेश के जरिए विद्यार्थी को एक बेहतर इंसान के रूप में विकसित करने की दिशा में लगातार अथक प्रयास कर रही है। सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों के मानवीय मूल्यों का विकास करना और उन्हें देश का एक उत्तरदायी नागरिक बनाना है। सरकार के कुल वार्षिक बजट का लगभग एक चौथाई हिस्सा स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए तथा दिल्ली में शिक्षा से संबंधित बुनियादी सुविधाओं में विकास के लिए रखा गया है। बजट व्यय का लक्ष्य शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, शिक्षकों में उच्च कौशल सृजित करना, नवाचारी शिक्षण विधियों को प्रोत्साहित करना तथा खेल कूद प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है।

1.4 शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कुल 1053 सरकारी स्कूलों का प्रबंधन करता है। इनमें विशेषज्ञता प्राप्त उत्कृष्टता विद्यालय (एसओएसई) और 204 सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय शामिल हैं। लगभग 18 लाख विद्यार्थियों और 70,111 शिक्षकों के नामांकन के साथ निदेशालय यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि सभी बच्चों को समान शिक्षा उपलब्ध हो सके। शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित विद्यालय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सर्वोदय बाल विद्यालय (एसबीवी)/कन्या विद्यालय (एसकेवी), राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, उत्कृष्टता विद्यालय और विशेषज्ञता प्राप्त उत्कृष्टता विद्यालय (एसओएसई) में वर्गीकृत किए गए हैं। शिक्षा निदेशालय ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिल्ली में प्रत्येक बच्चे को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो और सरकारी

विद्यालय शहर के निजी विद्यालयों के समकक्ष काम कर सकें, अनेक नवाचारी योजनाएं और पहल लागू की हैं।

1.5 शिक्षा निदेशालय का लक्ष्य दिल्ली में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, सतत और समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराना है। यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हाल के वर्षों में कई नई पहल की गई हैं। इनमें बुनियादी ढांचा सुविधाओं में सरकारी स्कूलों का विकास और आसपास के माहौल को बेहतर बनाना, अध्यापन कला में सुधार, सतत संपर्क प्रयासों से माता–पिता/समुदाय को शामिल करना, गहन शिक्षक प्रशिक्षण और सबसे बढ़ कर लक्षित शिक्षण विधियों से सीखने में कठिनाई वाले बच्चों की मदद करना और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना, शिक्षण सामग्री और आकलन साधनों की री–डिजाइनिंग शामिल है।

1.6 दिल्ली के शिक्षा मॉडल की, न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में व्यापक सराहना हो रही है। स्कूली शिक्षा प्रणाली में शिक्षण से संबंधित अभिनव रणनीतियों ने दिल्ली के शिक्षा मॉडल को अनूठा बना दिया है, जिसके माध्यम से पढ़ाई लिखाई को अधिक रुचिकर और आनंददायक बना कर बच्चों के शिक्षण अनुभव में लगातार सुधार लाया जा रहा है। हैपीनेस पाठ्यक्रम ने बच्चों में सहानुभूति, विवेकपूर्ण सोच विचार, समस्याओं को हल करने का तरीका, समाज में सार्थक संबंध विकसित करने के लिए संवाद और सहयोग जैसे कौशल विकसित करने में मदद की है। स्कूलों में चुनौती, मिशन बुनियाद, प्रगति, शिक्षण सामग्री, स्पोकन इंग्लिश कक्षाएं जैसे कई गुणवत्तापूर्ण सुधार कार्यक्रमों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

1.7 बुनियादी ढांचा सुविधाओं के विकास के तहत लगभग 8000 से अधिक अतिरिक्त क्लास रूम बनाए गए हैं और इनमें कक्षाएं चल रही हैं। अन्य 12000 अतिरिक्त क्लासरूम का निर्माण कार्य तेजी से जारी है और मार्च 2022 तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है। लगभग 20 नए स्कूल भवनों का निर्माण अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ पूरा हो चुका है। 23 और स्कूल भवन का निर्माण कार्य शुरू होने की प्रक्रिया में है। 728 स्कूल भवनों में से 577 में सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम पूरा हो चुका है। 146 स्कूल भवनों को गिरा देने या उनमें व्यापक मरम्मत कराने का प्रस्ताव है और शेष पांच स्कूल भवन का कार्य शुरू किया जाना है। वर्तमान विद्यालयों में भी अवसंरचना विकास का कार्य चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है।

1.8 कोविड–19 महामारी के दौरान शिक्षा निदेशालय ने विद्यार्थियों तक ऑनलाईन कक्षाओं के माध्यम से पहुंच बनाई। शैक्षणिक ड्यूटी निभाने के अलावा अध्यापकों ने कोरोना योद्धाओं की अनुकरणीय भूमिका भी निभाई।

1.9 बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार का सुचारू माहौल सृजित करने के लिए माता–पिता, बच्चों और शिक्षकों के बीच व्यापक बैठकों के आयोजन, स्कूल प्रबंधन समितियों के पुनर्गठन से सद्भावपूर्ण संबंध विकसित किया गया है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और स्कूल लीडर्स को विश्व के कुछ सर्वाधिक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से सीखने का अवसर प्रदान किया गया है। इनमें अन्य संस्थानों के अलावा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय और एनआईई सिंगापुर शामिल हैं। शिक्षा

क्षेत्र में सरकार के सतत और अथक प्रयासों से परीक्षा परिणामों में सरकारी स्कूलों के बच्चों के पास होने का प्रतिशत काफी बढ़ा है। वर्ष 2020–21 में यह सेकेंडरी स्तर पर (98 प्रतिशत) और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर (100 प्रतिशत) रहा।

1.10 शिक्षा क्षेत्र में सरकार की रणनीतियों से गुणवत्तापूर्ण सुलभ शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित हो रही है। स्कूल ड्रॉपआउट को रोकना तथा विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति में सुधार लाना संभव हुआ है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के पैटर्न पर राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण के लिए शिक्षण परिणामों का समय समय पर आकलन किया जा रहा है तथा शिक्षा विज्ञान और पाठ्यक्रम में लगातार शोध और सुधार के प्रयास जारी हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए उच्च कौशल प्राप्त और प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर पर नामांकन में बढ़ोतरी के प्रयास किए जा रहे हैं और प्रति वर्ष शिक्षा क्षेत्र को वार्षिक बजट का सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित किया जा रहा है।

1.11 (i) शिक्षा क्षेत्र में निवेश से इस क्षेत्र को मुख्य प्राथमिकता देने का सरकार का निर्णय निम्नलिखित विवरण 15.1 से स्पष्ट है।

विवरण 15.1

दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र.स.	वर्ष	शिक्षा पर व्यय	कुल बजट	कुल बजट में व्यय की प्रतिशत हिस्सेदारी	प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली का जीएसडीपी	दिल्ली के जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय
1	2014-15	6554.82	30940.10	21.19	494803	1.32
2	2015-16	7755.89	35195.52	22.03	550804	1.41
3	2016-17	9119.24	37263.36	24.47	616085	1.48
4	2017-18	9947.54	40926.85	24.31	677900	1.47
5	2018-19	10613.32	46245.89	22.95	738389	1.44
6	2019-20	11829.23	51186.26	23.11	794030	1.49
7	2020-21 (आर.ई.)	12113.79	59000	20.53	785341	1.54
8	2021-22 (बी.ई.)	15707.35	69000	22.76	923967	1.70

स्रोत : बजट दस्तावेज और अर्थशास्त्र सांख्यिकी निदेशालय (डीईएस)

(ii) खेल–कूद तथा कला और संस्कृति सहित शिक्षा का कुल व्यय (योजना और गैर–योजना) 2014–15 में 6555 करोड़ रुपये था, जो 2021–22 में बढ़ कर 15707 करोड़ रुपये हो गया। दिल्ली सरकार के कुल बजट में शिक्षा क्षेत्र पर व्यय 2014–15 के 21 प्रतिशत से बढ़ कर 2021–22 में 23

प्रतिशत हो गया। वर्ष 2021–22 में शिक्षा क्षेत्र पर व्यय दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.70 प्रतिशत था। शिक्षा पर व्यय में वर्षवार वृद्धि चार्ट 15.1 में दर्शायी गई है।

चार्ट 15.1

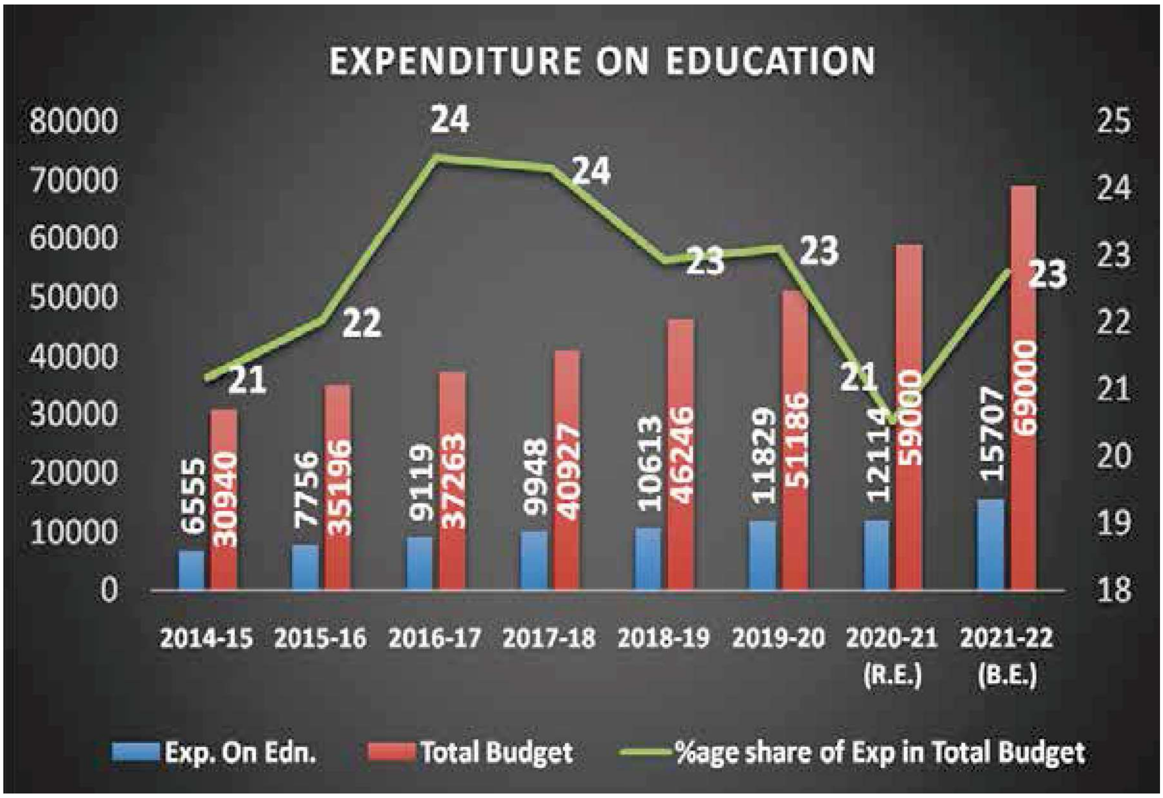

शिक्षा पर राज्यों का खर्च–भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्यों के बजट विश्लेषण के अनुसार

2.1 भारतीय रिजर्व बैंक की राज्य बजट विश्लेषण रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि देश के सभी राज्यों में से रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा क्षेत्र पर व्यय कर रही है। 2021–22 के दौरान दिल्ली शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट अनुमान के 22.8 प्रतिशत के साथ शीर्ष पर था। इसके बाद असम (18.6 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (18.1 प्रतिशत) का स्थान था। 2021–22 में राष्ट्रीय औसत 13.9 प्रतिशत था।

2.2 राज्यों के बजट विश्लेषण पर रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में दिल्ली का बजटीय आवंटन सर्वाधिक है। नीचे दिए गए विवरण 15.2 में पिछले 7 वर्षों में कुछ राज्यों के समग्र व्यय में से शिक्षा पर हुए खर्च का हिस्सा प्रदर्शित किया गया है।

विवरण 15.2

समग्र व्यय के अनुपात में शिक्षा पर व्यय

(प्रतिशत में)

क्र. स.	राज्य	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (आर ई)	2021-22 (बी ई)
1.	गुजरात	15.2	15.2	14.5	14.1	14.0	13.7	14.3	12.8
2.	हरियाणा	16.9	12.3	13.7	13.4	13.2	13.5	13.2	13.5
3.	कर्नाटक	14.3	13.6	12.5	12.0	11.4	12.4	12.0	11.8
4.	केरल	16.4	16.0	16.2	16.3	15.1	15.2	12.0	13.5
5.	महाराष्ट्र	19.2	19.2	17.7	17.0	15.6	17.2	15.0	15.5
6.	असम	24.7	25.5	22.0	21.6	21.8	19.4	17.2	18.6
7.	हिमाचल प्रदेश	17.7	16.3	15.2	17.6	16.5	16.2	16.4	17.2
8.	छत्तीसगढ़	20.2	18.6	19.6	18.5	17.4	18	18.5	18.1
9.	तमिलनाडु	15.8	15.5	13.0	14.4	13.9	15	13.3	12.2
10.	उत्तर प्रदेश	15.0	15.5	16.7	14.8	12.4	14.6	12.8	12.5
11.	**दिल्ली**	**21.2**	**21.8**	**24.2**	**24.2**	**22.8**	**23.1**	**20.5**	**22.8**
	अखिल भारत	16.0	15.3	14.7	15.0	14.4	15.2	14.3	13.9

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक वेबसाइट में राज्य बजट विश्लेषण (नवंबर 2021) रिपोर्ट

3. साक्षरता

3.1 साक्षरता दर, 7 वर्ष और ऊपर के लोगों में साक्षर लोगों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक व्यक्ति, जो पढ़ सकता है और किसी भी भाषा में सरल संदेश, उसे समझते हुए लिख सकता है, उसे साक्षर माना जाता है।

3.2 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में साक्षरता दर 86.2 प्रतिशत थी। इसमें पुरुष साक्षरता दर 90.9 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 80.8 प्रतिशत थी। यह 73 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर थी, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.9 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 64.6 प्रतिशत थी। दिल्ली में साक्षरता में स्त्री–पुरुष अंतराल 2001 के 12.62 प्रतिशत से कम होकर 2011 में 10.1 पर आ गया।

3.3 राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग (एनएसओ), भारत सरकार ने ''परिवार सामाजिक उपभोग : शिक्षा'' पर एनएसएस की 75वीं रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें 8000 गांवों और 6000 शहरी प्रखंडों में 1. 13 लाख परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है। यह रिपोर्ट जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच प्राप्त डेटा पर आधारित है और 7 वर्ष या ऊपर के आयुवर्ग के लिए है।

3.4 75वीं एनएसएस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली 88.7 प्रतिशत साक्षरता दर के साथ केरल के बाद दूसरे स्थान पर है। दिल्ली में पुरुष साक्षरता दर 93.7 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 82.4 प्रतिशत है। ये दोनों दरें अखिल भारतीय साक्षरता दर से अधिक हैं। देश की औसत साक्षरता दर 77.7 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 84.7 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 70.3 प्रतिशत है।

3.5 दिल्ली में साक्षरता में लगातार सुधार हो रहा है और इसके साथ ही साक्षरता अंतराल कम हो रहा है। यह सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए सुधार के लिए शिक्षा क्षेत्र में किए गए अथक प्रयासों का परिणाम है। महिला और पुरुष दोनों साक्षरता दर में बढ़ोतरी का रुख है। 1991 में 75.29 प्रतिशत की साक्षरता दर बढ़ कर 2011 में 86.2 प्रतिशत हो गई और वर्ष 2017–18 में और बढ़ोतरी के साथ 88.7 प्रतिशत पर पहुंच गई। लेकिन पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच 11 प्रतिशत का अंतराल अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है, जिसका समाधान करना जरूरी है।

4. शैक्षिक संस्थानों का नेटवर्क और सभी प्रबंधन द्वारा संचालित स्कूलों में नामांकन

सभी प्रकार के प्रबंधन जैसे स्थानीय निकायों, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और निजी क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थानों के नेटवर्क की जानकारी विवरण 15.3 में दर्शायी गयी है :

विवरण 15.3

क्र सं	संकेतक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	शैक्षिक संस्थान							
	पूर्व प्राथमिक+प्राथमिक	2806	2779	2735	2745	2718	2682	2653
	मिडिल	933	940	933	905	872	867	855
	माध्यमिक	385	393	400	374	367	359	357
	वरिष्ठ माध्यमिक	1674	1684	1704	1736	1769	1783	1801
	कुल	**5798**	**5796**	**5772**	**5760**	**5726**	**5691**	**5666**
2.	**स्कूलों में नामांकन** (लाख में)							
	पूर्व प्राथमिक+प्राथमिक	20.83	21.02	20.83	20.63	20.79	21.08	20.01
	मिडिल	11.16	11.20	11.27	11.21	11.23	11.39	11.53
	माध्यमिक	6.52	6.92	7.41	7.00	7.31	7.27	7.62
	वरिष्ठ माध्यमिक	5.62	5.16	4.92	5.09	4.86	5.02	5.63
	कुल	**44.13**	**44.30**	**44.43**	**43.93**	**44.19**	**44.76**	**44.79**
3.	अध्यापक							
	पूर्व प्राथमिक+प्राथमिक	29708	29577	28989	28048	27662	27040	26244
	मिडिल	11741	12315	12657	12392	12431	12905	11665
	माध्यमिक	9370	10292	9401	9512	9805	9829	9202
	वरिष्ठ माध्यमिक	88661	93909	97224	97291	105848	107944	104893
	कुल	**139480**	**146093**	**148271**	**147243**	**155746**	**157718**	**152004**
4.	**विद्यार्थी शिक्षक अनुपात**	**32**	**30**	**30**	**30**	**28**	**28**	**29**

स्रोत : शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

5. दिल्ली सरकार के शैक्षिक संस्थानों का नेटवर्क और पंजीकरण

5.1 दिल्ली में दिल्ली सरकार के अंतर्गत कुल 1231 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं, जो दिल्ली में चल रहे कुल स्कूलों का 21.73 प्रतिशत हैं। 2020–21 के दौरान सभी स्कूलों में कुल दाखिलों में सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों की हिस्सेदारी 39.36 प्रतिशत रही।

5.2 दिल्ली सरकार के अंतर्गत संचालित विद्यालयों की संख्या और नामांकन की स्थिति विवरण 15.4 में दी गई है।

विवरण 15.4

क्र सं	संकेतक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
क	**दिल्ली सरकार के स्कूलों की संख्या**	**1007**	**1011**	**1017**	**1019**	**1022**	**1026**	**1027**
	कुल नामांकन (लाख में)	15.42	15.09	15.28	14.81	14.98	15.19	16.20
	लड़के	7.40	7.14	7.18	6.91	7.01	7.13	7.74
	लड़कियां	8.02	7.95	8.10	7.90	7.97	8.00	8.46
ख	**सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या**	**211**	**211**	**211**	**208**	**207**	**204**	**204**
	कुल नामांकन (लाख में)	1.63	1.68	1.57	1.55	1.49	1.45	1.43
	लड़के	0.87	0.85	0.83	0.82	0.78	0.75	0.74
	लड़कियां	0.76	0.83	0.74	0.73	0.71	0.70	0.69

स्रोत : शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.सरकार

5.3 राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में स्वच्छता में सुधार, सुरक्षा, बिजली, शौचालय और पीने के पानी की सुविधा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। सभी स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा, शौचालय, चारदिवारी और बिजली कनेक्शन उपलब्ध हैं। नीचे दी गई तालिका से संकेत मिलता है कि खेलकूद मैदान और कम्प्यूटर जैसी कुछ सुविधाओं में सुधार की गुंजाइश है।

विवरण 15.5
दिल्ली के स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति

निम्नांकित सुविधाएं रखने वाले स्कूलों का प्रतिशत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
खेल का मैदान	85.8	87.4	87.37	88.06	85.89	88.28	93.27
बाउंडरी वाल	99.4	99.5	99.90	99.88	100	100	100.00
लड़कियों के लिए शौचालय	100	100	100	100	100	100	100.00
लड़कों के लिए शौचालय	100	100	100	100	100	100	100.00
पेयजल सुविधा	100	100	100	100	100	100	100.00
विद्युत कनेक्शन	99.9	99.9	99.90	100	100	100	100.00
कम्प्यूटर सुविधा	81	83.9	87.18	88.82	89.26	97.56	100.00

स्रोतः यूडीआईएसई 2020–21

6. सकल दाखिला अनुपात (जीईआर)/निवल दाखिला अनुपात (एनईआर)

6.1 सकल दाखिला अनुपात की गणना किसी निर्दिष्ट कक्षा या कक्षाओं के समूह में निर्दिष्ट आयु समूह के विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात के रूप में की जाती है। दूसरी ओर निवल दाखिला अनुपात निर्दिष्ट शैक्षिक स्तर के लिए आधिकारिक आयु समूह का दाखिला है, जो उस आयु समूह की संबंधित आबादी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है।

6.2 यूडीआईएसई+ रिपोर्ट के अनुसार, 2019–20 में दिल्ली में प्राथमिक शिक्षा में सकल दाखिला अनुपात शिक्षा के सभी स्तरों पर अखिल भारतीय स्तर की तुलना में अधिक है। विभिन्न स्तरों पर जीईआर नीचे दिया गया है–

विवरण 15.6
शिक्षा वर्ष 2019–20 में सकल नामांकन अनुपात

शिक्षा स्तर	दिल्ली			अखिल भारत		
	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
प्राइमरी	118.36	122.80	120.38	101.87	103.69	102.74
अपर प्राइमरी	120.53	125.18	122.74	88.93	90.46	89.67
एलिमेंट्री	119.19	123.71	121.28	96.99	98.65	97.78
सेकेंडरी	108.09	112.92	110.31	77.97	77.83	77.90
हायर सेकेंडरी	68.98	77.50	72.82	50.52	52.40	51.42

स्रोत : यूडीआईएसई +रिपोर्टें

6.3 निवल नामांकन अनुपात (एनईआर) : नीचे दी गई तालिका में यह देखा जा सकता है कि निवल दाखिला अनुपात–एनईआर में पिछले वर्षों में दिल्ली की स्थिति में सुधार आया और यह 2019–20 के दौरान सभी स्तरों पर राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। इस प्रकार विवरण 15.6 और 15.7 दर्शाते हैं कि दिल्ली जीईआर और एनईआर के संदर्भ में अखिल भारतीय आंकड़ों से काफी आगे है।

विवरण 15.7

शैक्षणिक वर्ष 2019–20 में निवल नामांकन अनुपात

शिक्षा का स्तर	दिल्ली			अखिल भारत		
	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
प्राइमरी	100	100	100	90.52	92.37	91.40
अपर प्राइमरी	93.28	98.26	95.68	70.44	71.89	71.14
एलिमेंट्री	100.00	100.00	100.00	89.66	91.28	90.44
सेकेंडरी	69.71	75.38	72.32	50.17	50.30	50.23
हायर सेकेंडरी	44.41	51.09	47.43	31.42	33.26	32.30

6.4 75वें एनएसएस सर्वेक्षण (जुलाई 2017–जून 2018) के अनुसार दिल्ली और अखिल भारत का निवल उपस्थिति अनुपात विवरण 15.8 में दर्शाया गया है।

विवरण : 15.8

शिक्षा का स्तर	दिल्ली (ग्रामीण+शहरी)			अखिल भारत (ग्रामीण+शहरी)		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
प्राइमरी	92.8	85.5	89.8	86.8	85.1	86.1
अपर प्राइमरी	80.3	65.8	73.1	72.5	71.8	72.2
सेकेंडरी	57.9	71.0	62.4	57.9	57.3	57.6
हायर सेकेंडरी	56.0	50.9	54.0	43.9	42.7	43.4
पोस्ट हायर सेकेंडरी	20.3	27.5	23.4	21.1	17.6	19.4

विवरण 15.8 और चार्ट 15.2 दर्शाते हैं कि दिल्ली का निवल उपस्थिति अनुपात (एनएआर) सभी स्तरों पर अखिल भारतीय एनएआर से अधिक है।

चार्ट 15.2

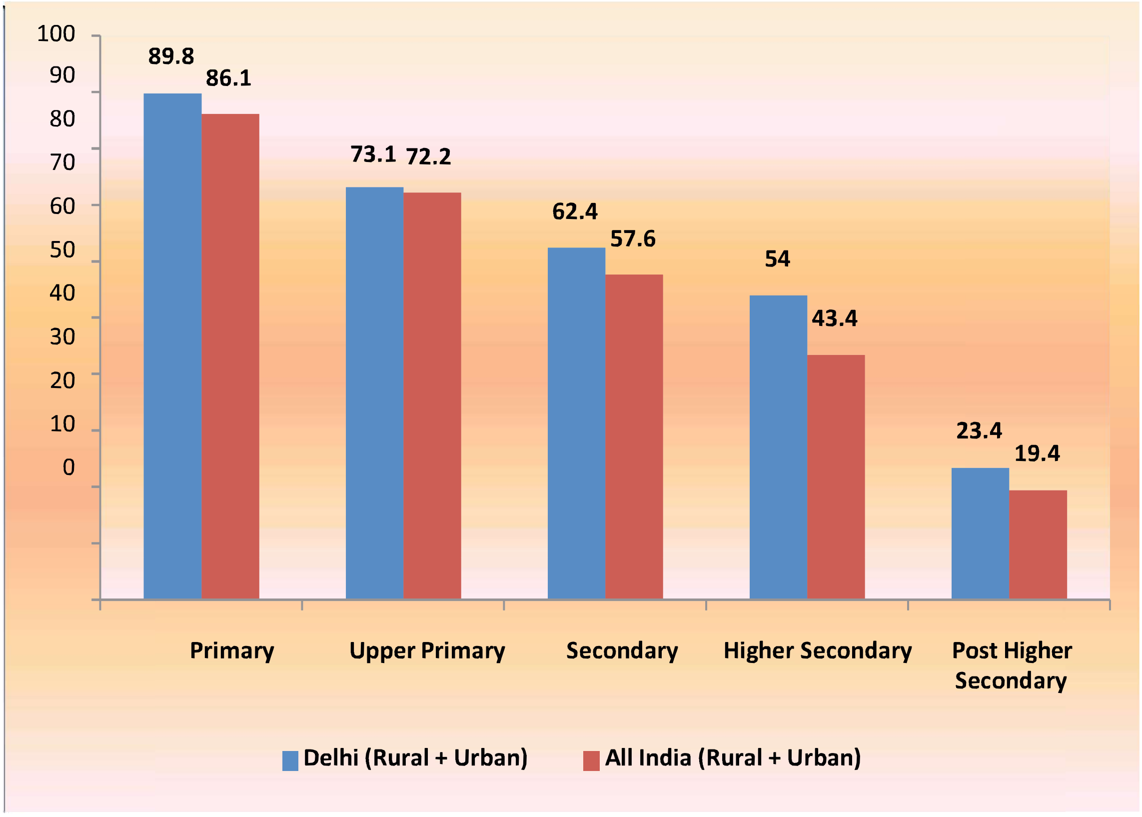

7. विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियां

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शैक्षणिक उपलब्धियों और परिणामों के आकलन के लिए कराया जाता है ताकि प्राथमिक स्कूल शिक्षा प्रणाली में सुधार लाया जा सके। एनएएस रिपोर्ट 2017 के अनुसार दिल्ली में कक्षा 3 और कक्षा 5 के विद्यार्थियों का प्रदर्शन गणित, पर्यावरणीय अध्ययन और साथ ही भाषा में राष्ट्रीय औसत से नीचे था। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इन सभी तीन क्षेत्रों में लड़कियों ने लड़कों की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन किया। इसे विवरण 15.9 में दर्शाया गया है।

विवरण 15.9

दिल्ली में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में विद्यार्थियों की सही प्रतिक्रिया का विषयवार हिस्सा (प्रतिशत)

निम्नांकित में प्रवीणता	दिल्ली			राष्ट्रीय औसत		
	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
तीसरी कक्षा						
गणित	54	54	54	64	64	64
पर्यावरण विज्ञान	55	56	55	64	65	65
भाषा	57	59	58	67	68	68
पांचवीं कक्षा						
गणित	43	45	44	54	54	54
पर्यावरण विज्ञान	48	50	49	57	57	57
भाषा	50	54	52	58	59	58
आठवीं कक्षा						
भाषा	53	56	55	56	57	57
गणित	32	32	32	42	42	42
विज्ञान	34	34	34	44	44	44
सामाजिक विज्ञान	34	36	36	44	44	44

स्रोत : दिल्ली राज्य शिक्षण रिपोर्ट, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2017

8. सकल नामांकन में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी

वर्ष 2014–15 से 2020–21 के दौरान दिल्ली में स्कूली शिक्षा में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी विवरण 15.10 में दर्शायी गई है।

विवरण : 15.10

स्कूली शिक्षा में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी

वर्ष	स्कूल (नामांकन लाख में)	प्राथमिक और मिडल	माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक	कुल
2014-15	निजी स्कूल	9.94	3.53	13.47
	कुल दाखिले	31.99	12.14	44.13
	कुल दाखिलों में निजी स्कूलों की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	31.07	29.08	30.52
2015-16	निजी स्कूल	10.34	3.62	13.96
	कुल दाखिले	32.22	12.08	44.30
	कुल दाखिलों में निजी स्कूलों की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	32.09	29.96	31.51
2016-17	निजी स्कूल	14.06	3.69	17.75
	कुल दाखिले	32.10	12.33	44.43
	कुल दाखिलों में निजी स्कूलों की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	43.80	29.93	39.95
2017-18	निजी स्कूल	14.51	3.81	18.32
	कुल दाखिले	31.85	12.08	43.93
	कुल दाखिलों में निजी स्कूलों की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	45.56	31.54	41.70
2018-19	निजी स्कूल	14.94	3.87	18.81
	कुल दाखिले	32.03	12.17	44.20
	कुल दाखिलों में निजी स्कूलों की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	46.64	31.80	42.56
2019-20	निजी स्कूल	15.17	3.92	19.09
	कुल दाखिले	32.47	12.29	44.76
	कुल दाखिलों में निजी स्कूलों की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	46.72	31.90	42.65
2020-21	निजी स्कूल	13.85	3.97	17.82
	कुल दाखिले	31.54	13.26	44.80
	कुल दाखिलों में निजी स्कूलों की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	43.91	29.94	39.78

स्रोत : शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

विवरण 15.10 में दर्शाए गए आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि दिल्ली में प्राइमरी और मिडिल स्तर पर कुल नामांकन में निजी स्कूलों की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई और यह वर्ष 2014–15 के 31.07 प्रतिशत से बढ़ कर 2019–20 में 46.72 प्रतिशत हो गई और 2020–21 के दौरान कम होकर 43.91 प्रतिशत पर आ गई। जबकि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर पर नामांकन में हिस्सेदारी वर्ष 2014–15 के 29.08 प्रतिशत से बढ़ कर 2019–20 में 31.90 प्रतिशत हो गई और 2020–21 के दौरान यह कम होकर 29.94 प्रतिशत पर आ गई।

9. दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कार्य निष्पादन – उत्तीर्णता प्रतिशत

2015–2021 के दौरान दिल्ली में माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक दोनों ही स्तरों पर विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने की प्रतिशत संबंधी सूचना विवरण 15.11 में दी गयी है :

विवरण 15.11

दिल्ली और भारत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड –सीबीएसई के परिणामों का उत्तीर्णता प्रतिशत : 2015–2021

क्र स	क्षेत्र/कक्षा स्तर	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.								
दिल्ली	माध्यमिक	95.81	89.25	92.44	68.90	71.58	82.61	97.52
	वरिष्ठ माध्यमिक	88.11	88.91	88.27	90.64	94.24	97.92	99.84
2.								
अखिल भारत	माध्यमिक	97.32	96.21	93.06	86.70	91.10	91.46	99.04
	वरिष्ठ माध्यमिक	82.00	83.05	82.02	83.01	83.40	88.78	99.37

स्रोत : दिल्ली स्टेटिस्टिकल हैंडबुक, 2021 और दिल्ली शिक्षा निदेशालय रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

उपरोक्त विवरण से अनुमान लगाया जा सकता है कि वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर दिल्ली का उत्तीर्णता प्रतिशत पिछले सात वर्षों के दौरान अखिल भारतीय स्तर से ऊंचा रहा है। माध्यमिक स्तर पर यह राष्ट्रीय स्तर की तुलना में कम है। माध्यमिक स्तर पर अपेक्षाकृत मामूली नतीजे संबंधिक शैक्षिक स्तर/कक्षाओं में सीखने में परिणाम मूलक गुणवत्ता की कमी को दर्शाते हैं। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के सीखने के कौशल में सुधार के लिए सरकार ने 'चुनौती', 'मिशन बुनियाद' 'प्रगति अध्ययन सामग्री, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, हैपीनेस पाठ्यक्रम इद्यादि शुरू किए हैं और इनके गुणवत्ता पूर्ण परिणाम मिलने लगे हैं।

विवरण 15.12
स्कूली शिक्षा क्षेत्र में निवेश

(करोड़ रुपये में)

क्र. स	वर्ष	शिक्षा पर व्यय	दिल्ली का कुल बजट	कुल बजट में शिक्षा व्यय की प्रतिशत	वर्तमान मूल्यों पर दिल्ली का जीएसडीपी	दिल्ली के जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में शिक्षा व्यय
1.	2014-15	6145.03	30940.10	19.86	494803	1.24
2.	2015-16	7178.57	35195.52	20.40	550804	1.30
3.	2016-17	8561.85	37263.36	22.98	616085	1.39
4.	2017-18	9208.77	40926.85	22.50	677900	1.36
5.	2018-19	9837.51	46245.89	21.27	738389	1.33
6.	2019-20	11081.09	51186.26	21.65	794030	1.40
7.	2020-21 (सं.अ.)	11205.00	59000	18.99	785342	1.43
8.	2021-22 (ब.अ.)	14346.49	69000	20.79	923968	1.55

स्रोत : बजट दस्तावेज और डीईएस

2021–22 में दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में शिक्षा व्यय सर्वाधिक 1.55 प्रतिशत है।

10 शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी व्यय

दिल्ली में सरकार द्वारा प्रति विद्यार्थी वार्षिक खर्च 2015–16 में 42,806 रुपये था जो वर्ष 2020–21 में बढ़कर 63,556 रुपये हो गया। शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी व्यय के बारे में वर्ष वार जानकारी विवरण 15.13 में दी गयी है।

विवरण 15.13
दिल्ली में शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी व्यय

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (आर.ई.)
व्यय (प्रति वर्ष)	42806	50812	56288	59730	66593	63556

नोट : व्यय राजस्व और पूंजी दोनों के समग्र व्यय पर आधारित है।

11. 2020–21 के दौरान स्कूली शिक्षा की उपलब्धियां

परिणाम

i) शिक्षासत्र 2020–21 के दौरान दिल्ली सरकार के स्कूलों में 12वीं के स्तर पर उत्तीर्णता प्रतिशत 99. 84 प्रतिशत रहा। जबकि 2019–20 में यह 97.92 प्रतिशत था।

ii) शिक्षासत्र 2020–21 के दौरान दिल्ली सरकार के स्कूलों में 10वीं के स्तर पर उत्तीर्णता प्रतिशत 97.52 प्रतिशत रहा। जबकि 2019–20 में यह 82.61 प्रतिशत था।

प्रशिक्षण–

i) 2020–21 के दौरान एससीईआरटी द्वारा इन हाउस और एसएसए प्रायोजित मॉड्यूल के तहत नवनियुक्त एचओएस और शिक्षकों को गहन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण लेने वालों की संख्या 220351 थी।

ii) मार्गदर्शक–शिक्षक (मेंटर–टीचर) कार्यक्रम का परिणाम स्कूल स्तर पर अनुदेशों की गुणवत्ता में सुधार के लिए बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला रहा।

ii) शिक्षा निदेशालय के स्कूलों के सभी शिक्षकों को अध्ययन सामग्री से ऑनलाईन उपयोग और विद्यार्थियों की उपस्थिति, उनके शैक्षणिक प्रदर्शन और सीखने की कमियों की निगरानी के लिए टैबलेट दिए गए।

11.2 समग्र शिक्षा (एसएस)

समग्र शिक्षा भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसके तहत शिक्षकों की भर्ती, बुनियादी ढांचा, प्रशिक्षण, पाठ्य पुस्तकें इत्यादि उपलब्ध कराने के लिए सहयोग दिया जाता है। वर्ष 2018–19 से 3 सीएसएस स्कीम–एसएसए, आरएमएसए और शिक्षक शिक्षा स्कीम समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत लाई गई हैं। इस योजना का उद्देश्य समयबद्ध ढंग से सबके लिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करा कर प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना है।

i) स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्यधारा में लाने के लिए 834 विशेष प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी), स्थापित किए गए हैं।
ii) एसएसए के तहत 60154 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।
iii) एसटीसी में 24729 बच्चों को नामांकित किया गया है।

ईडब्ल्यूएस प्रवेश

i) वर्ष 2019–20 के दौरान शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और सुविधा वंचित श्रेणी के 35962 विद्यार्थियों को ऑनलान लाटरी द्वारा चयन के आधार पर गैर–सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में प्रवेश दिया गया है। 2020–21 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत प्रवेश की संख्या 35275 हो गई है।

नई पहल

सभी पक्षों– विद्यार्थियों, माता–पिता और शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी से सर्वोत्तम गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित पहल किए गए हैं।

i) **दिल्ली स्कूली शिक्षा बोर्ड**

दिल्ली स्कूली शिक्षा बोर्ड की शुरूआत मार्च 2021 में की गई। दिल्ली के स्कूलों में सर्वोत्तम शिक्षा और आकलनों के लिए बोर्ड ने अंतरराष्ट्रीय बैकालॉरेट (आईबी) से साझेदारी की। बोर्ड ने दिल्ली सरकार के 30 स्कूलों के साथ अपना कामकाज शुरू कर दिया है। अगले कुछ वर्षों में दिल्ली सरकार के सभी स्कूल और इच्छुक निजी स्कूल डीबीएसई से संबद्ध हो सकते हैं।

डीबीएसई का उद्देश्य अध्ययन आकलन क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाना है। पूरे विश्व से शिक्षण क्षेत्र में सर्वोत्तम अनुभवों को आधार बनाकर और इस क्षेत्र के विशेषज्ञ भागीदारों को साथ लेकर डीबीएसई नर्सरी से 12वीं कक्षा तक अध्ययन आकलनों की रूपरेखा तय करेगा।

ii) विशेषज्ञता प्राप्त उत्कृष्टता विद्यालय (एसओएसई)

विशेषज्ञता प्राप्त उत्कृष्टता विद्यालय, विश्वस्तरीय स्कूल हैं जो विशेष अध्ययन क्षेत्र में गहन रूचि रखने वाले विद्यार्थियों की मदद करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से प्रेरित ये स्कूल विद्यार्थियों को अपनी पूरी क्षमता की पहचान करने में सहयोग देते हैं। वर्तमान समय में 20 विशेषज्ञता प्राप्त उत्कृष्टता विद्यालय अपने शुरूआती वर्ष में कार्यरत हैं और एसटीईएम, मानविकी विज्ञान, प्रदर्शन और दृश्य कला तथा 21वीं सदी के आधुनिकतम कौशल क्षेत्र में लगभग 2300 विद्यार्थियों के साथ कार्य कर रहे हैं। अपने चुनाव पर आधारित ये स्कूल ग्रेड 9 से 12वीं तक के लिए हैं।

एसओएसई के पाठ्यक्रम और आकलन माध्यम नए दौर, उच्च प्रौद्योगिकी अवसंरचना और सुदृढ शिक्षण फैकल्टी के साथ हैं। शिक्षण फैकल्टी के सदस्यों को वैश्विक और स्थानीय शिक्षा विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण प्रदान किया है। ये विद्यालय प्रमुख विश्वविद्यालयों, विशेषज्ञों और उद्योग जगत के प्रमुखों के साथ भागीदारी में इंटर्नशिप, प्रशिक्षुता, मास्टर क्लास, अतिथि व्याख्यान और संबंधित क्षेत्र के अध्ययन भ्रमण के माध्यम से शिक्षा को और समृद्ध बना रहे हैं। एसओएसई विद्यार्थियों को बहुत छोटी उम्र से ही विशेषज्ञता प्राप्त करने का माध्यम उपलब्ध कराकर उन्हें उच्च शिक्षा और आकांक्षी करियर के लिए तैयार करते हैं।

iii) **बिजनेस ब्लास्टर**

बिजनेस ब्लास्टर परियोजना 11वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के लिए उद्यमिता रूचि वाले विद्यार्थियों के लिए एक व्यावहारिक कार्यक्रम है। इसके तहत प्रति विद्यार्थी 2000 रुपए की सीड मनी दी जाती है ताकि वे टीम में काम करें और वास्तविक जीवन में अपनी उद्यमिता रूचि को लागू करते हुए किसी बिजनेस आइडिया को कार्यान्वित कर सकें। लगभग 60 करोड़ रुपए की सीड पूंजी के साथ 1000 सरकारी स्कूलों के लगभग तीन लाख विद्यार्थियों ने अपने नवाचारों के साथ इस परियोजना में भाग लिया। 24 टीमों को दिसंबर 2021 में प्रसारित टेलीविजन शो बिजनेस ब्लास्टर में भाग लेने का मौका भी मिला। इस कार्यक्रम के दौरान उन्हें निर्णायकों से 50 हजार रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की निवेश राशि प्राप्त हुई।

iv) **देशभक्ति पाठ्यक्रम**

दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में 28 सितंबर 2021 से देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरूआत हुई। इसका उद्देश्य बच्चों को अपने गौरवशाली इतिहास और संस्कृति की जानकारी देकर सच्चे अर्थों में

देशभक्त बनाना है। यह के–12 नागरिकता पाठ्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान में निहित मूलभावना, भाईचारे, सहनशीलता और समानुभूति का समावेश करना है और विद्यार्थियों में सामूहिक एकजुटता की भावना का संचार करना है।

देशभक्ति पाठ्यक्रम अनुदेशक संचालित पाठ्यक्रम है, जिसमें क्लासरूम में विद्यार्थियों को देश के प्रति प्रेम और आदर के विषय पर परिचर्चा करने का अवसर मिलता है। देश की शक्तियों और चुनौतियों की पहचान कर वे इस बात का आकलन करने में समर्थ होते हैं कि देश की प्रगति के लिए उनका योगदान क्या हो सकता है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को बिना किसी हिचक या बाधा के अपने विचार, मत और अनुभव साझा करने के योग्य बनाना है।

v) **विद्यार्थी–मेंटर कार्यक्रम (शिक्षा के लिए युवा कार्यक्रम)**

इस कार्यक्रम का शुभारंभ 11 अक्तूबर 2021 को किया गया था। इसका उद्देश्य युवाओं के एक ऐसे समुदाय का गठन करना है जो विद्यार्थियों को अपने करियर, अपने मत और प्रतिदिन के चुनाव के बारे में खुला संवाद करने में सक्षम बना सके। कार्यक्रम का लक्ष्य सक्रिय युवाओं की भागीदारी से देश के भविष्य को आकार देना है। इसके लिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को उनके समग्र विकास के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। इस संदर्भ में कार्यक्रम प्रबंधन इकाई गठित की गई है।

vi) **पैरेंट आउटरीच प्रोग्राम**

एसएमसी, माता–पिता, बच्चों के बीच का अंतराल कम से कम करने और समुदाय के सहयोग से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरू 28 अक्तूबर 2021 को की गई थी। एसएमसी मित्र/माता–पिता समूहों के सदस्य के बीच प्रभावी संपर्क के लिए लगभग 50 विद्यार्थियों के माता–पिता के साथ एक एसएमसी मित्र/सदस्य के साथ कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का गठन किया गया है।

vii) **समावेशी शिक्षा**

वर्ष 2020–21 के दौरान बीच में स्कूल छोड़ने वाले 251 दिव्यांग बच्चों को घर पर ही शिक्षा उपलब्ध कराई गई। वर्ष 2021–22 में दिल्ली के दक्षिणी, दक्षिण पूर्व और दक्षिण–पश्चिम जिलों में सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे दिव्यांग बच्चों की चिकित्सकिय आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से लगभग 2200 ऐसे बच्चों की पहचान की गई है।

वर्ष 2021–22 (दिसंबर 2021 तक) के दौरान उपलब्धियां

1 सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लाभ के लिए स्कूल ऑनलाईन कक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं। संपर्क से वंचित रह गए विद्यार्थियों तक पहुंचने के लिए अनेक रचनात्मक उपाय किए गए।

2 वर्ष 2021–22 के दौरान 21 विद्यालयों में साइंस स्ट्रीम और 5 स्कूलों में वाणिज्य विषय की शुरूआत की गई।

3 विद्यार्थियों को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विषयों का व्यापक चुनाव विकल्प उपलब्ध कराने के लिए 90 स्कूलों में अतिरिक्त नए विषयों की शुरूआत की गई।

4 शिक्षा निदेशालय ने आर्थिक रूप से कमजोर और सुविधा वंचित वर्ग के बच्चों के प्रवेश के लिए केंद्रीयकृत ऑनलाइन ड्रॉ का संचालन किया। लगभग 40336 विद्यार्थियों ने मान्यता प्राप्त निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश लिया।

5 वर्ष 2021–22 के दौरान दिसंबर 2021 तक 4022 नए क्लासरूम निर्मित किए गए और लोक निर्माण विभाग द्वारा शिक्षा निदेशालय को सौंपे गए।

6 कोविड महामारी के कारण स्कूल बंद किए जाने पर दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और एमसीडी स्कूलों के नर्सरी से लेकर 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को सूखे राशन का किट उपलब्ध कराया।

7 दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में 28 सितंबर 2021 को देशभक्ति पाठ्यक्रम लागू किया गया।

8 देश का मेंटर प्रोग्राम दिल्ली सरकार द्वारा लागू किया गया है। इसका उद्देश्य 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को उनके समग्र विकास के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है।

9 बिजनेस ब्लास्टर परियोजना के तहत लगभग 3 लाख विद्यार्थियों को 2000 रूपए प्रति विद्यार्थी की दर से सीड मनी उपलब्ध कराई गई है ताकि वह अपने नवाचारों के साथ आगे आकर अपना बिजनेस आइडिया कार्यान्वित कर सकें।

10 दिल्ली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (डीबीएसई) का गठन किया गया है और बोर्ड ने दिल्ली के तीस सरकारी स्कूलों के साथ अपना काम शुरू कर दिया है।

11 वर्ष 2021–22 के दौरान 20 विशेषज्ञता प्राप्त उत्कृष्टता विद्यालय शुरू किए गए। ये एसटीईएम, मानविकी विज्ञान, प्रदर्शन और दृश्यकला तथा 21वीं सदी के नवीनतम कौशल के क्षेत्र में लगभग 2300 विद्यार्थियों के साथ काम कर रहे हैं। अपने चयन पर आधारित ये स्कूल ग्रेड 9 से ग्रेड 12वीं तक के लिए हैं।

12 वर्ष 2021–22 के दौरान पुस्तकों/पत्र पत्रिकाओं/ई पुस्तकों की खरीद के लिए शिक्षाविदों/शिक्षाविद प्रशासकों को अनुदान उपलब्ध कराने की नई योजना शुरू की गई, ताकि वे दिल्ली के स्कूलों और कक्षाओं को अपना सर्वोत्तम देने के लिए अपने ज्ञान का संवर्द्धन कर सकें।

13. उच्च शिक्षा

13.1 राज्य सरकार का विशेष ध्यान युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना और उन्हें रोजगार पाने योग्य बनाना है। दिल्ली में उच्च शिक्षा प्रणाली में हाल के वर्षों में प्रभावी वृद्धि का रुख रहा है और यही प्रवृत्ति अगले वित्तय वर्षों में भी बने रहने की संभावना है। सरकार गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा पर ध्यान दे रही है। इसके लिए सुलभ शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों तक पहुंच मे सुधार किया जा रहा है। हाल में उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और विकास को बढावा देने, इन्क्यूबेशन केंद्रों के गठन और विद्यार्थियों में उद्यमिता प्रतिभा विकसित करने के लिए कई नवाचारी कार्यक्रम शुरु किए गए हैं। कौशल विकास संवर्धन सरकार के लिए उच्च प्राथमिकता का क्षेत्र है। सरकार का उद्देश्य संस्थानों को उन्नत कर वैश्विक मानदंडों के अनुरूप बनाना है।

बजट में उच्च शिक्षा के लिए आवंटन बढ़ा कर वर्ष 2020–21 के 415.50 करोड़ रुपये से 2021–22 के लिए 594.43 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

13.2 दिल्ली में वर्ष 2020–21 में कुल 222 उच्च शिक्षा संस्थान थे। जिनका ब्योरा नीचे दिया गया है–

विवरण 15.14

दिल्ली में उच्च शिक्षा संस्थान

क्र सं	संस्थान	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	विश्वविद्यालय	11	12	12	12	13	13	14
2.	विश्वविद्यालय के रूप में समकक्ष संस्थान	12	12	11	11	11	11	9
3.	राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान	3	3	4	4	4	4	5
4.	सामान्य शिक्षा संबंधी कॉलेज	81	84	84	85	90	90	91
5.	व्यावसायिक शिक्षा संबंधी कॉलेज	100	100	102	107	100	100	103
	कुल	**207**	**211**	**213**	**219**	**218**	**218**	**222**

स्रोत :डीएचई–एआईएसएचई पोर्टल 2019–20 तथा विश्वविद्यालय वेबसाइट

नोट : कॉलेजों की संख्या में वृद्धि/कमी वर्ष विशेष में कॉलेजों को संबद्धता दिए जाने के कारण है।

13.3 विवरण 15.14 से पता चलता है कि दिल्ली में उच्च शिक्षा संस्थानों में से करीब 46 प्रतिशत व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं की श्रेणी में आते हैं. इसके बाद करीब 41 प्रतिशत संस्थान सामान्य शिक्षा संस्था श्रेणी में और बाकी 13 प्रतिशत विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं।

विवरण 15.15
उच्च शिक्षा में कुल दाखिले (2017–18 से 2019–20)

(लाख में)

वर्ष	उच्च शिक्षा में कुल दाखिले		महिलाओं के दाखिले		दखिलों में महिलाओं का प्रतिशत	
	दिल्ली	अखिल भारत	दिल्ली	अखिल भारत	दिल्ली	अखिल भारत
2017-18	10.64	366.42	4.99	174.37	46.89	47.58
2018-19	10.77	373.99	5.28	181.89	49.02	48.63
2019-20	11.33	385.36	5.54	188.93	48.89	49.02

स्रोत : *उच्च शिक्षा के बारे में अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) पोर्टल 2019–20*

13.4 विवरण 15.15 से स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन बढ़ता जा रहा है

विवरण 15.16
उच्च शिक्षा में विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रमों में स्त्री–पुरुष समानता सूचकांक (जीपीआई)

	2019-20	
स्तर	दिल्ली	अखिल भारत
स्नातक	0.90	0.97
स्नातकोत्तर	1.45	1.32
स्नातकोत्तर डिप्लोमा	0.79	0.87
एम.फिल.	1.03	1.65
पी–एच.डी	0.85	0.82
डिप्लोमा	0.79	0.54
सर्टिफिकेट	0.68	1.16
एकीकृत	0.50	0.78

स्रोत : उच्च शिक्षा में नामांकन के बारे में अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) रिपोर्ट 2019–20 के आंकड़ों के आधार पर परिकलित

13.5 स्त्री–पुरुष समानता सूचकांक (जीपीआई) उच्च शिक्षा में दाखिला लेने वाली महिलाओं का पुरुषों की तुलना में अनुपात है। यह शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर स्त्री–पुरुष समानता की दिशा में प्रगति का पैमाना है और समाज में महिलाओं के सशक्तीकरण को दर्शाने वाला महवत्पूर्ण संकेतक है। इस सारिणी से स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली में स्नातकोत्तर, पी.एच.डी. और डिप्लोमा स्तर पर जीपीआई राष्ट्रीय औसत से बेहतर है।

13.6. 2020–21 में उच्च शिक्षा क्षेत्र की महत्वपूर्ण बातें

पूंजी परियोजना:

- **सूरजमल विहार में गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के नए पूर्वी परिसर का निर्माण कार्य** : परियोजना का 95 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। परियोजना के 2022 में पूरा हो जाने की संभावना है।

- **नया परिसर– अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली : विश्वविद्यालय के दो नए परिसर धीरपुर और रोहिणी में 20 हेक्टेयर और 7.3 हेक्टेयर भूमि के आवंटित प्लॉट पर बनाए जाने की योजना है। इनके लिए** परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई है। मास्टर प्लान, स्कीम, डिजाइन और नए प्रस्तावित निर्माण की रूपरेखा की तैयारी मास्टर प्लान दिल्ली 2021 के अनुसार चल रही है। धीरपुर परिसर पूरा हो जाने के बाद इसमें 16040 विद्यार्थियों और रोहिणी परिसर में 9900 विद्यार्थियों के समायोजित होने का अनुमान है।

- **दिल्ली खेलकूद विश्वविद्यालय** : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अपने घोषित लक्ष्य के अनुरूप दिल्ली खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना की है। इसका उद्देश्य खेल–कूद शिक्षण प्रशिक्षण, शारीरिक गतिविधियां, मनोरंजन और युवा विद्यार्थियों का शारीरिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना है। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य विभिन्न खेलकूद क्षेत्रों में तथा स्वास्थ्य और व्यायाम जैसे सहयोगी विषयों में खेलकूद, शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों का संवर्द्धन करना है। खेलकूद विश्वविद्यालय अधिनियम सरकारी गजट में अधिसूचित कर दिया गया है।

- वर्तमान में दिल्ली खेलकूद विश्वविद्यालय लुडलो कैसल खेलकूद परिसर से संचालित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के उप–कुलपति और रजिस्ट्रार की नियुक्ति वर्ष 2021–22 में हो चुकी है। इसके लिए मुंडका के निकट हिरनकूदना गांव में लगभग 80 एकड़ की जमीन उच्च शिक्षा निदेशालय को, माननीय उपराज्यपाल की अनुमति के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय को हस्तांतरित कर दी गई है।

- **दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय** – मंत्रिपरिषद ने दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक पर मसौदा कैबिनेट नोट का अनुमोदन कर दिया है। और दिल्ली विधानसभा ने जनवरी 2022 में इसे पारित कर दिया है। दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय अधिनियम 2022, 10 जनवरी 2022 को अधिसूचित किया जा चुका है। विश्वविद्यालय का स्थाई परिसर गांव बक्करवाला में लगभग 12 एकड़ जमीन पर

स्थापित किया जाना है। कुलपति, सह कुलपति, रजिस्ट्रार इत्यादि की नियुक्ति की प्रक्रिया उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की जा रही है।

- अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने इस वर्ष 4 नए कार्यक्रमों की शुरूआत की है। (i) नवाचार में स्नातकोत्तर व्यवसायिक प्रशासन, उद्यमिता और उपक्रम विकास (एमबीए–आईईवीडी), 53 सीटों की क्षमता के साथ (ii) स्नातकोत्तर कला, हिन्दी में, 53 सीटों की क्षमता के साथ (iii) व्यावसायिक प्रशासन स्नातक, 44 सीटों की क्षमता के साथ और (iv) स्नातक व्यवसायिक कार्यक्रम, लेखांकन और वित्त में, 40 सीटों की क्षमता के साथ।
- विश्वविद्यालय ने कोविड महामारी का फैलाव देखते हुए विद्यार्थी शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना की ताकि विद्यार्थियों की परिक्षाओं और अन्य अकादमिक गतिविधियों से संबधित समस्याओं का निपटान किया जा सके।
- महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा को मदद देने के लिए विश्वविद्यालय ने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को टैबलेट वितरित किए।

➢ **राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय :**

राष्ट्रीय आकलन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) ने 4 सूत्री पैमाने पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को ए ग्रेड की आधिकारिक मान्यता दी है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एनआईआरएफ रैंकिंग 2019 में विधि श्रेणी में दूसरा रैंक दिया गया है।

➢ **जीजीएसआईपीयू–**

- गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के तहत विभिन्न पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने वाले निजी प्रबंधन संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए फीस निर्धारण के उद्देश्य से 5वीं राज्य शुल्क नियामक समिति का गठन किया गया है। 5वीं राज्य शुल्क नियामक समिति ने विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क निर्धारण के बारे में अपनी मसौदा रिपोर्ट सौंप दी है।

डीएचई ट्रस्ट के तहत स्कीम

➢ **''दिल्ली उच्च शिक्षा सहायता ट्रस्ट''** : की वित्तीय सहायता योजना से सम्बद्ध प्रतिभा–सह माध्यम (मेरिट–कम–मीन्स) – इस योजना के तहत 9 राज्य विश्वविद्यालयों और उनके सम्बद्ध कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड रखने वाले विद्यार्थी अपनी ट्यूशन फीस के 100 प्रतिशत के बराबर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नहीं आने वाले विद्यार्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है, ट्यूशन फीस के 50 प्रतिशत के बराबर सहायता पा सकते हैं। 2.50 लाख रुपये से 6 लाख रुपये प्रति वर्ष की आमदनी वाले परिवार के विद्यार्थी ट्यूशन फीस के 25 प्रतिशत के बराबर लाभ पाने के पात्र होंगे। वर्ष 2020–21 के दौरान इस योजना के तहत 6820 विद्यार्थियों को 48.14 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई

गई। वर्ष 2019–20 के दौरान 3760 विद्यार्थियों को 24.01 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी।

➢ **दिल्ली उच्च शिक्षा और कौशल विकास ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट की दिल्ली उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना** – इस योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को, दिल्ली में और दिल्ली से बाहर (भारत में) के उच्च शिक्षा संस्थानों में उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए दिया जाता है। वर्ष 2020–21 के दौरान इस योजना के तहत 13 विद्यार्थियों को 66.9 लाख रुपये की राशि वित्तीय सहयोग के रूप में मंजूर की गई। इस योजना के तहत 2021–22 के दौरान (दिसंबर 2021 तक) दो विद्यार्थियों को 10.37 लाख रूपए स्वीकृत किए गए हैं।

14 तकनीकी शिक्षा

14.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने युवाओं को कौशल विकास और ज्ञान संवर्द्धन के लिए उत्तम अवसर प्रदान किए हैं। सरकारी संस्थानों में इसके लिए सीटों की संख्या बढाई गई है। 2015 में सभी सरकारी पॉलिटेक्निक (नया नाम प्रौद्योगिकी संस्थान) में स्नातक कार्यक्रम व्यवसायिक पाठ्यक्रम (बी. वीओसी) शुरू किया गया है। बी.वीओसी के विद्यार्थियों के लिए दिल्ली सरकार ने 2019–20 में तीन प्रौद्योगिकी संस्थान में वोकेशनल पाठ्यक्रम में मास्टर कार्यक्रम की शुरूआत की है। प्रत्येक संस्थान में विद्यार्थियों की संख्या 25 है।

14.2 दिल्ली सरकार ने तकनीकी शिक्षा में छह राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। ये हैं– दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू), इंदिया गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय (आईजीडीटीयूडब्ल्यू), इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी दिल्ली संस्थान (आईआईआईटी–डी), दिल्ली औषधि विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय (डीपीएसआरयू), नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एनएसयूटी) और दिल्ली कौशल उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीएसईयू)। इनके अलावा प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक डिग्री स्तर का संस्थान (कला महिविद्यालय) भी है। विभिन्न तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या पिछले पांच वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाई गई है। इसे विवरण 15.17 में दर्शाया गया है।

14.3 तकनीकी शिक्षा दिल्ली सरकार की नीतियों में प्राथमिकता के रूप में उभरी है। सरकार ने सरकारी सुलभ और गुणवत्तापूर्ण तकनीकी व्यवसायिक और तृतीयक शिक्षा, कौशल विकास तक युवाओं की पहुंच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है, ताकि उन्हें अच्छे रोजगार और उद्यमिता से जोड़ा जा सके।

14.4 दिल्ली में 6 राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय (विवरण नीचे दिया गया है) और 77 तकनीकी संस्थान हैं। तकनीकी शिक्षा में प्रवेश चाहने वालों की तुलना में सीटों की उपलब्धता हमेशा एक चुनौती रही है। दिल्ली सरकार इस समस्या के समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए अधिक विद्यार्थियों को शामिल करने की क्षमता में वृद्धि के लिए उपलब्ध संसाधनों और बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है। रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार ने हाल के वर्षों में कई पहल की हैं,

जिनमें 25 विश्वस्तरीय कौशल विकास केंद्रों की स्थापना, विद्यार्थियों को प्रवेश देने की क्षमता बढ़ाना, फैकल्टी विकास कार्यक्रम शामिल हैं।

1) **दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू),** जो पहले दिल्ली कॉलेज आफ इंजीनियरिंग (डीसीई) के नाम से जाना जाता था, दिल्ली में एक राज्य विश्वविद्यालय है। वर्ष 1941 में इसकी स्थापना दिल्ली पॉलिटेक्निक के रूप में की गई थी। 1952 में दिल्ली विश्वविद्यालय से आधिकारिक मान्यता प्राप्त होने के बाद इसने डिग्री प्रदान करने की शुरुआत की। वर्ष 2009 में इस कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम दिया गया। इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और उभरते सहयोगी क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करना है तथा इन्क्यूबेशन, उत्पाद विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उद्यमिता के लिए एक पारिस्थितिकीय प्रणाली को बढ़ावा देना है। विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में इस विश्वविद्यालय की प्रवेश क्षमता 2021–22 के दौरान 5100 विद्यार्थी है।

2) **नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एनएसयूटी)**, पहले नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान (एनएसआईटी) के रूप में जाना जाता था। यह द्वारका दिल्ली में स्थित एक राज्य विश्वविद्यालय है। 2018 में इस संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और इसका नाम बदल कर नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रमों के माध्यम से शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देना है तथा अनुसंधान और विकास क्षेत्र में नई जानकारी उपलब्ध कराना है। इस विश्वविद्यालय का प्राथमिक मिशन समाज और देश की सेवा के लिए क्षमतावान, नवाचारी और अग्रणी मार्गदर्शक तैयार कर वैश्विक पहचान का एक प्रमुख विश्वविद्यालय बनना है, जो शिक्षा, अनुसंधान और विकास में उत्कृष्टता स्थापित करे। वर्ष 2021–22 के दौरान इस विश्वविद्यालय की प्रवेश क्षमता 2788 विद्यार्थी है।

3) **दिल्ली औषधि विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय (डीआईपीएसआरयू)**, देश का पहला फार्मेसी विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार के वर्ष 2008 के अधिनियम 7 के तहत की गई थी। विश्वविद्यालय का लक्ष्य औषधि विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान का एक उत्कृष्ट केंद्र बनना है और बड़े पैमाने पर लोगों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। विश्वविद्यालय का प्राथमिक मिशन अग्रणी मार्गदर्शक, प्रशासक और कर्मी तैयार करना है, जो औषधि विज्ञान के पेशेवरों के रूप में अपना उत्तरदायित्व निभा सकें तथा स्वास्थ्य से संबंधित संस्थानों, उद्योगों और समुदायों के उपयुक्त हों। इस विश्वविद्यालय की प्रवेश क्षमता वर्ष 2021–22 में 1097 है।

4) **इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय (आईजीडीटीयूडब्ल्यू)**, की स्थापना 1998 में इंदिरा गांधी संस्थान के रूप में हई थी। दिल्ली सरकार के प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसकी स्थापना की थी। मई 2013 से इंदिरा गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान ने दिल्ली सरकार के तहत पहले महिला प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल कर लिया और इसका नाम बदल कर इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। यह विश्वविद्यालय 4 क्षेत्रों में

प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में स्नातक शिक्षा उपलब्ध कराता है – ये क्षेत्र हैं – कम्प्यूटर साइंस और इंजीनियरी (सीएसई), इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी (ईसीई), सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), मेकेनिकल और ऑटोमेशन इंजीनियरीग (एमएई)। यह स्थापत्यकला में स्नातक पाठ्यक्रम, विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा पी.एचडी डिग्री प्रदान करता है। वर्ष 2021–22 के दौरान इस विश्वविद्यालय की प्रवेश क्षमता 1275 है।

5) **दिल्ली इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी–डी),** की स्थापना दिल्ली अधिनियम 2007 के तहत 2008 में की गई थी। इसे अनुसंधान और विकास तथा डिग्री प्रदान करने का अधिकार सौंपा गया। ये संस्थान शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत में सर्वाधिक प्रतिबद्ध संस्थानों में एक है। बहुत कम समय में इस संस्थान ने सुदृढ़ शोध संस्कृति विकसित की है और नवाचारी शिक्षा कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया है। आईआईटी की दिल्ली में वर्तमान समय में 6 विभाग कार्यरत हैं – कम्प्यूटर साइंस, इलेक्ट्रानिक्स और संचार, कम्प्यूटेशनल बायोलॉजी, मानव केंद्रित डिजाइन, सामाजिक विज्ञान और ह्यूमेनिटीज तथा गणित। ये संस्थान सतत विकास और रूपांतरण की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है तथा वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थान का दर्जा हासिल कर रहा है। वर्ष 2021–22 के दौरान इस विश्वविद्यालय की प्रवेश क्षमता 878 है।

6) दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीएसईयू) की स्थापना 15 अगस्त 2020 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य कौशल शिक्षा कार्यक्रमों को डीएसईयू की देखरेख के तहत लाना है। आरंभिक कदम के रूप में सभी डब्ल्यूसीएससी और सरकारी प्रौद्योगिकी संस्थान (जो पहले पॉलिटेक्निक कहे जाते थे) अब डीएसईयू में आ गए हें। इसके अलावा दो कॉलेज– जीबीपीजीईसी और डीआईटीई भी विश्वविद्यालय के साथ मिला लिए गए हैं, नई शिक्षा नीति 2020 की आवश्यकता के अनुसार संस्थान को नया रूप देते हुए। डीएसईयू उद्योग संबंधी पाठ्यक्रम की मांग पर और संस्थानों के साथ उद्योग गतिविधियां मजबूत करने पर काम कर रहा है। वर्ष 2021–22 के दौरान इसकी प्रवेश क्षमता 6258 विद्यार्थियों की है।

प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा निदेशालय के तहत कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता विवरणी 15.17 में स्पष्ट परिलक्षित होती है। प्रवेश क्षमता 2015–16 में 6026 से बढ़ कर 2021–22 में 17396 हो गई है, जो 188 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

विवरण–15.17
कॉलेजों और विश्वविद्यालय में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता

क्र सं	संस्थान	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) (पूर्वी परिसर सहित)	2534	2843	3689	3814	3790	5000	5100
2	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एनएसयूटी)	1005	1033	1051	1175	1521	1696	2788
3	इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय (आईजीडीटीयूडब्ल्यू)	564	689	689	618	710	1113	1275
4	इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगकी संस्थान दिल्ली (आईआईआईटी–डी)	337	444	546	612	660	859	878
5	जीबी पंत राजकीय इंजीनियरीग कॉलेज (जीबीपीजीईसी)	225	225	180	210	220	NIL	--
6	आम्बेडकर उच्च संचार प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान (एआईएसीटीएंडआर)	252	252	252	252	270	--	--
7	चौधरी ब्रह्म प्रकाश राजकीय इंजीनियरीग कालेज (सीएच. बीपीजीईसी)	185	148	120	134	180	250	--
8	दिल्ली उपकरण इंजीनियरीग संस्थान (डीआईटीई)	258	258	258	138	140	180	--
9	दिल्ली भेषज विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान (डीआईपीएसएआर)	227	215	235	241	150	--	--
10	दिल्ली भेषज विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय (डीपीएसआरयू)	156	175	173	310	410	530	1097
11	कला महाविद्यालय (सीओए)	283	231	239	343	343	402	NIL
12	दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय	-	-	-	-	-	-	6258
	कुल	**6026**	**6513**	**7432**	**7847**	**8394**	**10030**	**17396**

टिप्पणी :

1. एआईएसीटीएंडआर और सीएच. बीपीजीईसी एनएसयूटी के साथ मिला दिए गए हैं, और इनका डेटा एनएसयूटी में दर्शाया गया है।
2. डीआईपीएसएआर को डीपीएसआरयू के साथ मिला दिया गया है और डेटा डीपीएसआरयू में दर्शाया गया है।
3. डीआईटीई और जीबीपीईसी का विलय डीएसईयू में कर दिया गया है और डेटा डीएसईयू में दर्शाया गया है।

चार्ट 15.3

महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता

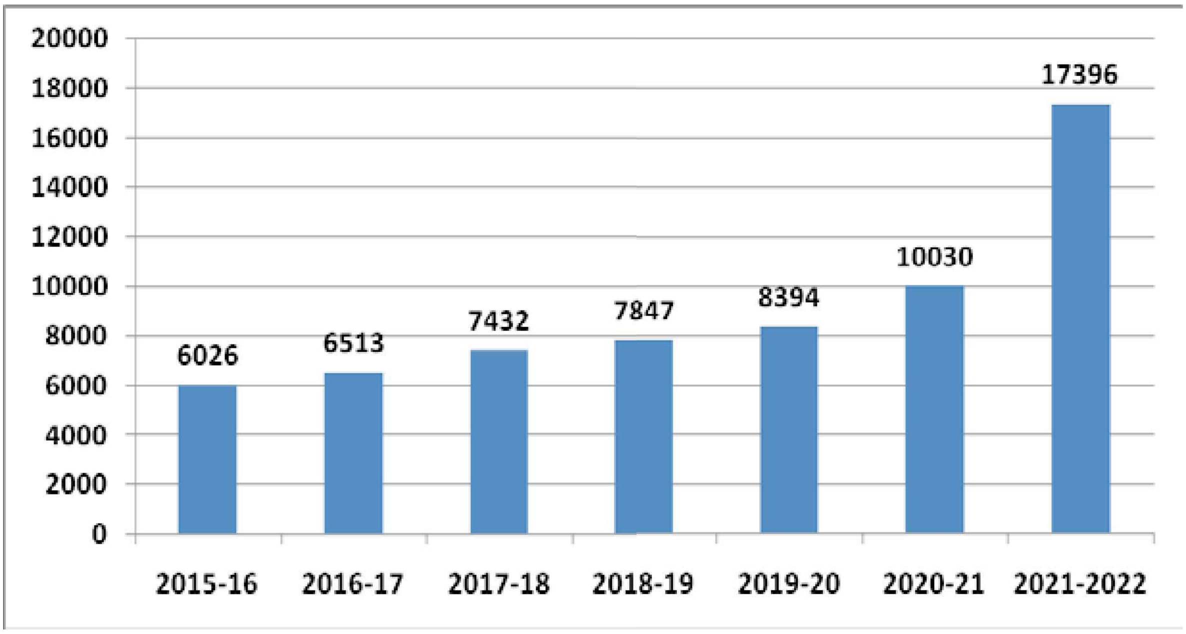

विवरण 15.18

2015–16 से 2021–22 के दौरान दिल्ली में तकनीकी संस्थान

क्र सं	तकनीकी संस्थान	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	17	19	19	19	19	19	19
2	औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र	61	63	63	63	40	33	33
3	प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र	1	1	1	1	1	NA	NA
4	व्यवसायिक संस्थान	1	1	1	1	1	--	--
5	प्रौद्योगिकी संस्थान (पॉलीटेक्निक)	20	19	19	19	19	18	10 (डीएसईयू में विलय) 08 (निजी)
6	विश्वस्तरीय कौशल उन्नयन केंद्र	1	1	1	7	7	7	7
कुल		101	104	104	110	87	77	77

स्रोत : तकनीकी शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

2015–16 से 2021–22 के दौरान तकनीकी संस्थानों में छात्रों की संख्या विवरण 15.19 में प्रस्तुत की गई है।

विवरण 15.19

2015–16 से 2021–22 के दौरान दिल्ली में तकनीकी संस्थानों में छात्रों की संख्या

क्र सं	तकनीकी संस्थान	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	11675	12771	11672	11792	10241	10960	11020
2	औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र	2610	4427	3747	3672	3720	6128	5478
3	प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र	530	681	680	754	765	NA	NA
4	व्यवसायिक संस्थान	90	118	0	0	0	--	-
5	प्रौद्योगिकी संस्थान (पॉलीटेक्निक)	16982	15568	14540	15023	16770	7934	637
6	विश्वस्तरीय कौशल उन्नयन केंद्र	363	630	612	683	690	NIL	-
कुल		**32250**	**34195**	**31251**	**31924**	**32186**	**25022**	**17135**

स्रोत : तकनीकी शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

टिप्पणी :

1. प्रौद्योगिकी संस्थान (पॉलिटेक्नीक) और डब्ल्यूसीएससी को वर्ष 2021–22 के दौरान डीईएसयू में मिला दिया गया।
2. पॉलिटेक्नीक में दर्शाय गए विद्यार्थी डीटीटीई के तहत 22–12–2021 से प्राइवेट संस्थान हैं।

चार्ट : 15.4

2015–16 से 2021–22 तक दिल्ली के तकनीकी संस्थानों में विद्यार्थियों की संख्या

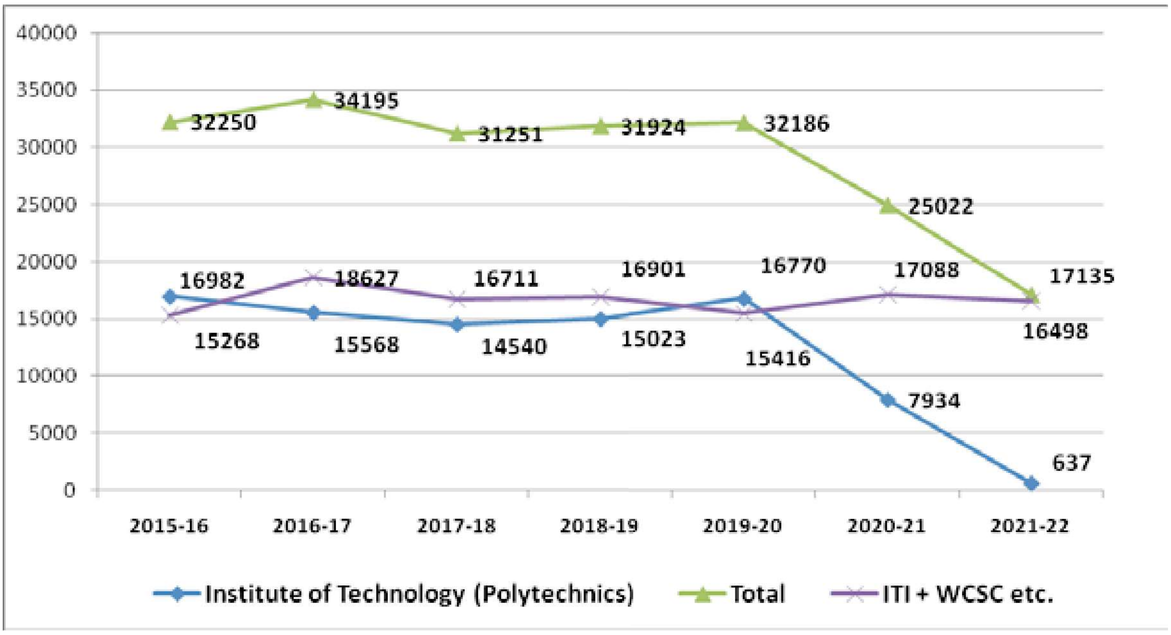

➢ **इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना**

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने युवाओं को नए उद्यमों की स्थापना (स्टार्ट अप्स) के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें रोजगार खोजने वाले की बजाए रोजगार देने में सक्षम बनाने के लिए राज्य

इन्क्यूबेशन नीति मंजूर की है। 11 इन्क्यूबेशन सेंटर पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक तकनीकी और उच्च शिक्षा संस्थान को अपेक्षित बुनियादी ढांचा कायम करने, कम्प्यूटरों आदि की खरीद और सहयोग एवं नवाचार का वातावरण बनाने के लिए 1.5 करोड़ रुपये दिए थे। इन्क्यूबेशन नीति की धारा 8 के अनुसार कंपनियों का गठन इन्क्यूबेटरों के लिए होल्डिंग कंपनी के रूप में किया गया है और प्रतिभागी संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर के लिए किया गया है ताकि परिसर के भीतर इन्क्यूबेशन सेंटरों की स्थापना में सहायता मिले। मौजूदा समय तक कुल 122 इन्क्यूबेट, इन केंद्रों में काम कर रहे थे। संस्थानवार सूची नीचे दी गई है–.

सरकारी सहयोग /कोष का उपयोग कर रहे विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों तथा संस्थानों में स्थापित इन्क्यूवेशन केंद्र/स्टार्टअप की अद्यतन स्थिति

क्र सं	इन्क्यूवेशन केंद्र का नाम	स्टार्टअप की संख्या	जारी सीड मनी
1.	एआईएसीटीआर इन्क्यूवेशन और अनुसंधान फाउंडेशन	5	1.52 करोड़
2.	स्टार्ट फाउंडेशन में एएनडीसी	13	1.71 करोड़
3.	एयूडी इन्क्यूवेशन इनोवेशन और उद्यमिता केंद्र	14	3.13 करोड़
4.	बीपीआईबीएस ज्ञान और नवाचार फाउंडेशन	3	1.66 करोड़
5.	डीपीएसआरयू इनोवेशन और इन्क्यूवेशन फाउंडेशन (डीआईआईएफ)	15	2.07 करोड़
6.	डीडटीयू इनोवेशन एंड इन्क्यूवेशन फाउंडेशन	19	1.86 करोड़
7.	आईजीडीटीयूडब्ल्यू–अन्वेषण फाउंडेशन	9	2.14 करोड़
8.	आईआईआईटी–दिल्ली इनोवेशन एंड इन्क्यूवेशन सेंटर	13	2.24 करोड़
9.	एनएसयूटी इन्क्यूवेशन एंड इनोवेशन फाउंडेशन (एनएसयूटी–आईआईएफ)	12	1.68 करोड़
10.	एसएससीबीएस इनोवेशन एंड इन्क्यूवेशन फाउंडेशन (एसआईआईएफ)	19	2.18 करोड़
11.	डीआईटीई		0.5 करोड़
	कुल	**122**	**20.69 करोड़**

टिप्पणीः वर्ष 2021–22 के दौरान कोई सीड मनी जारी नहीं की गई। इसलिए उपर्युक्त सूचना में, इन्क्यूवेशन सेंटर के संदर्भ में कोई बदलाव नहीं है।

2021–22 में तकनीकी शिक्षा के संदर्भ में प्रमुख उपलब्धियां

- शिक्षा के विभिन्न विषयों में कौशल शिक्षा में गुणवत्ता और विकास को बढ़ावा देने तथा जनसांख्यिकी का लाभ उठाने तथा आर्थिक विकास के उद्देश्य से रोजगार योग्य और प्रशिक्षित मानव संसाधन विकसित करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों की तैयारी और प्रशिक्षण के लिए दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीएसईयू) की स्थापना की गई। सभी विश्वस्तरीय

कौशल केंद्र, 10 प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली टूल इंजीनियरिंग संस्थान और जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत डीएसईयू में मिला दिए गए और विश्वविद्यालय की कुल प्रवेश क्षमता अकादमिक सत्र 2021–22 में 6258 हो गई।

- 76 कमरों का दो नया फैकल्टी ब्लॉक लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया और 16 फरवरी 2021 को दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इनका उद्घाटन किया गया। इसके बाद यह कमरे संबंधित विभागों को सौंप दिए गए, विश्वविद्यालय में फेज 2 के निर्माण कार्य के पहले चरण में 9 मंजिला दो ब्लॉक और 12 मंजिला तीन छात्रावास ब्लॉक बनाया गया। इससे तीन हजार विद्यार्थियों के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधा बढ़ेगी। 660 लड़कियों के लिए और 330 लड़कों के लिए अतिरिक्त छात्रावास इस वर्ष पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

- अंबेडकर उन्नत संचार प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान, गीता कॉलोनी और चौधरी ब्रह्मप्रकाश राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जफरपुर, नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एनएसयूटी) में मिला दिए गए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम व्याख्यान थियेटर परिसर एनएसयूटी में बनाया गया है। इसमें 11 स्मार्ट हॉल हैं, जिनमें 10 हॉल में, प्रत्येक में 125 विद्यार्थियों को समायोजित करने की क्षमता है और एक व्याख्यान हॉल 270 विद्यार्थियों की क्षमता का है।

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की पहल 'ध्यान और योग विज्ञान केंद्र' दिल्ली औषध विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय (डीपीएसआरयू) में शुरू किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 20 जून 2021 को इस केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र ध्यान और योग विज्ञान में एक वर्ष का डिप्लोमा प्रदान कर रहा है, जिसमें तीन महीने के बाद पाठ्यक्रम से निकलने और प्रमाणपत्र प्राप्त करने का विकल्प रहेगा। पहले बैच की ऑनलाईन कक्षा जून 2021 में शुरू हुई थी। 450 प्रशिक्षित और अभिप्रमानित अनुदेशकों के निर्देशों से लगभग 2000 नागरिक विभिन्न शिविरों में लाभान्वित हुए। इन शिविरों का आयोजन दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर 31 दिसंबर 2021 तक किया गया था।

- एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के साथ टीटीए के समझौता ज्ञापन पर फरवरी 2021 में हस्ताक्षर किया गया। यह समझौता औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जेल रोड और पूसा के बीच इलेक्ट्रिशियन, पलंबर, वेल्डर और कारपेंटर व्यवसाय में प्रशिक्षुओं को इंटर्नशिप के माध्यम से औद्योगिक अनुभव प्रदान करने के बारे में है।

- जीबी पंत एकीकृत परिसर 526 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत से तैयार किया जा रहा है। आशा है कि वर्ष 2023 तक यह काम पूरा हो जाएगा। इस परिसर में डीएसईयू के पाठ्यक्रम और अन्य गतिविधियां समायोजित होंगी।

- दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फेस–2 का निर्माण कार्य 292 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से लोक निर्माण विभाग द्वारा शुरू कर दिया गया था। अब यह पूरा होने के चरण में है। इससे कार्यशालाओं, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, महिला छात्रावास इत्यादि की जरूरत पूरी होंगी तथा नए पाठ्यक्रम शामिल करने और नए विद्यार्थियों के प्रवेश की क्षमता भी बढ़ेगी।